भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2350
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना

2350. श्री बालक नाथः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्ययोजना आरंभ करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त कार्ययोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षु बैंक ऋण लेकर अपना लघु उद्यम शुरू करने में समर्थ बनते हैं। आरएसईटीआई को पूरे

देश में जिले के अग्रणी बैंकों के माध्यम से चलाया जा रहा है और फिलहाल देश में 583 आरएसईटीआई हैं। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के 61 अनुरूपी व्यवसायों में प्रदान किए जाते हैं।

(ii) स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी):- इस योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में ग्रामीण गरीबों की मदद करना है। इसमें शुरूआती (स्टार्ट अप) पूंजी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उद्यमों को कारोबारी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्धन का एक संवर्ग स्थापित किया जाता है।

आरएसईटीआई कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक 23 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और स्व-रोजगार के लिए 16.63 लाख लोगों को नियोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आरएसईटीआई के कार्यान्वयन के लिए 100.02 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

एसवीईपी कार्यक्रम के लिए 31 अक्टूबर, 2019 तक 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों की वार्षिक कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 21 राज्यों के 120 ब्लॉकों में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (पीआर) अनुमोदित की जा चुकी हैं। अनुमोदित पीआर के अनुसार, 4 वर्षों की अवधि में 1.93 लाख उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक कुल 69,991 उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एसवीईपी के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

*****